मेट्रो को ट्रैक पर लाने की तैयारी

राज्य सरकार ने राइट्स से किया एमओयू

2016 तक पटना के एक हिस्से में मेट्रो दौड़ाने की योजना

8000 करोड़ रुपए पूरी योजना पर खर्च होने का अनुमान

राजधानी में मेट्रो ट्रेन के लिए सोमवार को एमओयू पर हस्ताक्षर करते नगर विकास सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ और राइट्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविन्द कुमार ।

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राजधानी पटना में मेट्रो दौड़ाने का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। इस वर्ष के अंत तक इस योजना का डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगा। राज्य सरकार ने इसकी जिम्मेदारी राइट्स को सौंपी है। सोमवार को राइट्स और राज्य सरकार के बीच एमओयू किया गया।

इस पर नगर विकास सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ और राइट्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविन्द कुमार ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर बुडको के एमडी अनुपम कुमार सुमन और नगर विकास विभाग के निदेशक जय सिंह मौजूद थे। राइट्स राजधानी में मेट्रो की संभावनाओं की तलाश करेगा। पटनासिटी व दानापुर के बीच लगभग 30 किलोमीटर के बीच मेट्रो की संभावना का अध्ययन होगा। सितम्बर तक राइट्स संभावना रिपोर्ट सौंपेगा जबकि दिसम्बर तक अंतिम डीपीआर सौंपेगा।

पिछले दिनों कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर सहमति की मुहर लगाई थी। राज्य सरकार वर्ष 2016 तक राजधानी के एक हिस्से में मेट्रो दौड़ाने की योजना पर काम कर रही है। इसीलिए प्रारंभिक बाधाओं को दूर करने के लिए बगैर लंबी प्रक्रिया के सीधे राइट्स से सहयोग लेने की योजना बनाई है। राइट्स ने देश के कई बड़े शहरों में मेट्रो परियोजना के लिए सर्वे का काम किया है। वह कई जगहों पर इस काम में जुटी हुई भी है। राइट्स राजधानी पटना में रूट-ट्रैकों के लिए संभावनाओं का पता लगाएगी।

जाम से मिलेगी निजात

राजधानी पटना की आंतरिक सड़कें बुरी तरह जाम हो रही हैं। इसके अलावा निकट से गुजरने वाली सड़कें, नेशनल हाइवे, बाइपास भी जाम की समस्या से पीड़ित हैं। घंटों जाम के कारण आम लोगों की भारी फजीहत हो रही है। पटना के आस-पास के लोगों की मजबूरी है कि वे पटना आने के लिए अपने वाहनों का ही प्रयोग करते हैं। लिहाजा सड़क पर बोझ अत्यधिक बढ़ गया है। मेट्रो-मोनो रेल होने से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा और सड़क पर दबाव कम होगा। इससे सड़कों पर लगने वाले जाम से भी छुटकारा मिलेगा और यातायात सुगम होगा।

JetScreenshot